1 2		3	4	5	6	
3. Kerosene						
(i) Superior	. Per litre at 15C	26,500	6.845*	33.345	 The incidence of additional excise duty is expected to be borne by the Oil Companies. 	
(ii) Inferior	. ,,	5.090	8.770*	13.860		
4. Petrol (Motor spirit)	,,	100.00	8.155*	108-155		
@5. Cotton fabrics (manu- Per sqaure factured in a com- metre			Fabric duty			
posite mill)	•	Yarn duty	Basic	Additional	Handloom	Total
(i) Medium-B-Gra	у	4.40	••	6.00	1.90	12:30
(ii) Coarse-Grey		2.30		3 60	1.90	7.70
-						

Reforms in Taxation System suggested by Minister of Heavy Industry

4275. SHRI MUHAMMED SHARIFF: SHRI SEZHIYAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- Government have (a) whether considered the question of reform in the Tax System in the country as suggested by Minister of Heavy Industry on 23rd June, 1973 in Hyderabad: and
 - (b) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): (a) and (b). In his speeches delivered at Hyderabad on the 23rd June 1973, Shri T. A. Pai, Minister of Heavy Industry did not make any suggestion for reforming the tax system as such Accordingly the question of considering any proposal in this regard does not arise.

सूरत जिले में पांच बीघा से कम भिम वालों को राष्ट्रीकृत बंकों द्वारा (देया गया ऋण

4276. श्री शमर सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्रो यह बताने की कुश करेंगे कि :

- (क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत दो वर्षों में सूरत जिले (गुजरात) में पांच बीघा से कम भूमि वालों को ऋण दिये हैं :
- (ख) क्या पांच बीघासे ग्रधिक भिम वालों को ऋण दिये गये हैं; ग्रीर
- (ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऋण दिये थे ग्रौर उनमें से प्रत्येक बैंक ने कूल कितना ऋष्ण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती स्त्रीलारोहतगी): (क) ग्रीर (ख): सरकारी

[@]In the case of sugar and cotton fabrics, additional excise duty is levied in lieu of sales tax

के बैंक, छोटे कृषकों की ग्रावश्यकताश्रों को पूरा करने पर विशेष जोर देरहे हैं।

(ग) सूरत जिले में कृषकों को दिये गये ऋणों के बैंक-वार ग्रांकडे ग्रभी उपलब्ध नहीं हैं। जुन 1972 के अन्त में सुरत जिले में अनुसुचित वाणिज्यिक बैंकों के 99 कार्यालयों में से जिन 86 कार्यालयों ने सूचना दी है उसके अनुसार कृषि (बागानों को छोडकर) को दिये गये स्रश्निमों की कूल बकाया रकम 1.29 करोड रुपये है।

पटसन का मृल्य निर्धारित करना

4277. श्री जानेश्वर प्रसाद यादव : क्या वा रिएडय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पटसन की ब्रागामी फसल में कितना उत्पादन होने की स्राशा है सौर पटसन की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत क्या होगी;
- (ख) क्या ट्रेड यूनियनों ने मां की है कि पटसन का मूल्य कम से कम 60 रुपये प्रति मन निर्धारित किया जाना चायि: ग्रीर
- (ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की या प्रतिकिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी • जाजं): (क) उद्योग तथा व्यापार को लगभग 75 लाख गांठों का उत्पादन होने की है। उत्पादन लागत 56.81 रु० तथा 7 3 रु० प्रति क्विंटल के बीच रहने का ग्रनमान लगायः गया है।

(छ) विभिन्न व्यापार संघों द्वारा विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं।

(ग) कृषि मूल्य ग्रायोग की सिकारिशों के ब्राधार पर सरकार ने इस मौसम के दौरान कच्चे पटसन (ग्रासःम बाटम किस्म) की न्युनतम समर्थन कीमत 125 रु० प्रति क्विंटल िश्चित की है। तथापि, 157.68 रु प्रति क्विंटल की ग्रीसत कीमत लाने की दृष्टि से भारतीय पटसन निगम को यथा एवं कच्चा पटसन खरीदने का सुझाव दिया गया है।

Breach of Promotion Policy Agreement entered into by L.I.C. with the Federation of L.I.C. Class I Officers Association in 1970

4278. SHRI G. P. YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Life Insurance Corporation has committed a breach of the promotion policy agreement entered into with the Federation of Life Insurance Corporation Class I Officers' Associations in 1970; and
 - (b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI-MATI SUSHILA ROHATGI): (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

Representations made by ex-Emergency Commissioned Officers Employed in L.I.C. for Benefit in Fixation of Seniority and Pay

4279. SHRI G. P. YADAV: the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the representations of the ex-Emergency Commissioned Officers re-employed in the L.I.C. of India for giving benefit in the fixation of seniority and pay, as is being given to the Ex-E.C.Os.